[श्री राजनारायण]

नेहरू विश्वविद्यालय की दुर्गति हो रही है वैसी दुर्गति, अगर हैदराबाद में विश्वविद्यालय बनता है, उसमें न हो । हमारे मित्र चले गए, मैंने कहा था यहां रहना--श्याम लाल कालेज में 3 प्रोफेसर 15 दिन पहले बिना किसी आरोप के निकाल दिए गए । रोज प्रोफेसर आते है, नुरुल हसन साहब कहते हैं हम विश्वविद्यालय ऐक्ट में तरमीम करेंगे वाइस-चान्सलर हमको रोज कहते है कि हमने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रपट दे दी है, शिक्षा मंत्रालय सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनता है ? नूरुल हसन साहब आज इस सदन पर ऐलान करें कि विश्वविद्यालय के जितने एफिलिएटेड कालेज हैं उनकी गवर्निंग बाडी किसी भी अध्यापक को इस तरह से नहीं निकाल सकती. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please finish.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, अभी एक मिनट बाकी है विद्यार्थियों की पढ़ने की सिक्योरिटी होनी चाहिए । उसी तरह से श्रीमन्, अगर हम नेशनल फिटनैस कोर के बारे में कुछ कहे नहीं, तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेंगे ।

प्रो० एस०नूरुल हसन : यह ज्यादती होगी ।

श्री राजनारायण : अगर नूरुल हसन साहब कहते हैं कि इस नेशनल फिटनैस कोर में जितने अध्यापक लगे हैं उनकी ठीक तरह से व्यवस्था करेंगे तो हम उस पर बोलना नहीं चाहेंगे । हम चाहते हैं यह विश्वविद्यालय हमारे देश के विद्यार्थियों को शिक्षा का जो उद्देश्य है वह दे । शिक्षा वही है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को समष्टि में मिला दे । वह शिक्षा है, नहीं तो नहीं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please take your seat.

DISCUSSION UNDER RULE 176 RE. NEW WHEAT PROCUREMENT POLICY OF THE GOVERNMENT

श्री भैरों सिंह शेखावत (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय गेहूं की नयी नीति के संबंध में कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shekhawat, I think you will take 15—20 minutes so that other hon'ble Members can also be . . .

श्री भैरों सिंह शेखावत : 25 मिनट लूंगा ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: . . . accommodated because you would like a good discussion. Others also will take some time.

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैं चाहता हूं जितना शार्ट हो सकता हूं उतना ही बोलूं । उपसभापति महोदय, मार्च, सन् 1973 का वह दिन देश के लिए दुर्भाग्य का दिन था जिस दिन सरकार ने गेहूं के व्यापार का सरकारीकरण करने की नीति की घोषणा की थी । आप सब जानते हैं, जिस दिन से यह घोषणा की गई उस समय से लेकर आज तक हमारा देश ऐसे आर्थिक संकट में फंस गया कि उसमें से निकलना न सरकार के लिए संभव हो रहा है और न जनता ही अपने प्रयास से उससे निकल पा रही है । 1973 की यह नीति सरकार ने प्रगतिशील तारों के दबाव में आकर ग्रहण की थी और 1974 में जब सरकार ने इस नीति की असफलता को स्वीकार कर लिया तो नयी नीति व्यापारियों से मिल कर बनाई गई । पहली नीति जो 1973 में बनाई गई थी उसमें सरकार ने अपना मुख्य लक्ष्य रखा था—

> "to help in the acquisition by the public agencies of a major portion of its marketed surplus of this commodity."

और दूसरी जो नई नीति बनाई उसमें भी सरकार ने यह घोषणा की थी कि—

> "main thrust of the policy is to have bulk procurement,"

अब इन दोनों आधार के ऊपर हम इस बात का अनुमान लगा लें कि कौन-सी नीति सफल हुई । जहां तक नयी नीति का संबंध है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नई नीति फेल हुई, और कल लोक सभा में जब देश के खाद्य मंत्री ने यह घोषणा की कि सरकार और नई नीति के ऊपर विचार कर रही है, उससे भी यह अर्थ निकलता है कि सरकार की नई नीति भी फेल हुई है । अब ऐसी स्थिति में, जो पिछला अनुभव है उस अनुभव के आधार पर यदि सरकार नई नीति की घोषणा करेगी तो मेरी मान्यता है कि उसमें कुछ सफलता मिलेगी ।

आज देश का उत्पादन घट रहा है और उत्पादन उस स्थिति में घट रहा है जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 2,679 करोड़ रुपया एग्रिकलचरल सैक्टर के ऊपर खर्च किया । 124.56 टन अनाज हमने इन पांच वर्षों में डिस्ट्रिब्यूट किया और 354.85 लाख हैक्टर इरीगेशन पोटेन्शियल जो चौथे प्लान के आरम्भ में था, वह 428.87 लाख हैक्टर हो गया और इसके उपरान्त भी हमारा उत्पादन घटा । अब सरकारी आंकड़ों से सिद्ध हो रहा है कि 1970-71 में 108 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था और 1971-72 में 105 मिलियन टन का उत्पादन हुआ । 1972-73 में 953 मिलियन टन का उत्पादन हुआ और 1973-74 के आंकड़े सरकार ने स्पष्ट रूप से नही बतलाये है । इतनी बात जरूर है कि 1972-73 के मुकाबले में 1974-75 में उत्पादन कम हुआ है । ये प्रश्न बड़ा गम्भीर है । इतना भारी इंवैस्टमेंट करने के बाद, इतना ज्यादा इरीगेशन पोटेन्शियल बढ़ाने के बाद, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद और इतना इम्पुट्स के ऊपर खर्च करने के बाद भी हमारा उत्पादन क्यों नहीं बड़ा, वह क्यों गिरा, इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । अगर हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो बाकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नही आयेगी ।

एग्रिकलचर प्रोड्क्शन में तीन चीजों के बारे में शिकायत होती है । हमें प्रोड्यूसर को तीन बात की गारन्टी देनी चाहिये । पहिली गारन्टी तो उसको फिकसिटी आफ टैन्योर की दी जानी चाहिये और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का फेर बदल नहीं किया जाना चाहिये । दुर्भाग्य से हर बार सीलिंग के नाम से एजेन्ट प्रोप्राइटरशिप को डिस्टर्ब करने के लिए कभी किसी राज्य की विधान सभा में या संसद के अन्दर कोई बिल के द्वारा या फिर किसी प्रकार की चर्चा के द्वारा उसके दिमाग में सन्देह पैदा कर देते हैं । हम इस तरह का सन्देह पैदा कर देते हैं कि मेरी जो होल्डिंग है, उस पर मैं अगर इंवेस्ट करूंगा, तो वह मेरे अधिकार में रहेगी या नहीं नहीं रहेगी ? इस तरह का सन्देह हमने आज किसान के दिमाग में पैदा कर दिया है ।

दूसरी जरूरी चीज यह है कि जो कुछ भी वह उत्पादन कर रहा है, उसका उसे रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा अथवा नहीं ? लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के खाद्य मंत्री बार बार घोषणा करते रहते हैं लेकिन क्या वे एक भी उदाहरण इस बात का बतला सकते हैं कि बोने के समय से पहिले ही कभी भी भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आज तक घोषणा की है ? इन दो चीजों का असर निश्चित रूप से उत्पादन पर पड़ता है और किसान के दिमाग में अनिश्चितता पैदा होती है और इस अनिश्चितता का असर उत्पादन पर पड़ता है ।

तीसरा प्रश्न यह पैदा होता है कि गेहूं के प्रश्न को लेकर किसान के दिमाग में यह भ्रम पैदा कर दिया गया है कि वह जो कुछ पैदा करता है उसकी रिम्यूनरेटिव प्राइस उसको नही मिलती है । उसको मार्केट प्राइस से भी कम मिलता है । सरकार उसके माल को कम दाम पर खरीदती है और इस वजह से उसको उसके माल का कास्ट प्राइस भी नहीं मिलता है । 1972 के अन्दर, जिस समय सरकार ने गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लिया था तो उसने किसान को गेहूं की कीमत 76 रुपया क्विन्टल दिया था और 1974 में उसने 105 रुपया क्विन्टल दिया । इस तरह से 29 रुपये का वैरियेशन

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

प्रति क्विंटल हुआ । अब आप दूसरे साइड पर जाइये । सरकार ने 105 रुपया क्विन्टल के हिसाब से उसका गेहूं खरीदा और माननीय मंत्री जी ने अपनी घोषणा करके गेहूं की सीलिंग प्राइस 150 रुपया क्विन्टल कर दी । इस तरह से 45 रुपया प्रति क्विन्टल का अन्तर आ गया । इसका मतलब यह हुआ कि आप मार्केट प्राइस से कम दाम पर किसान का गेहूं लेना चाहते है । इसका परिणाम आज यह हो रहा है कि किसान आज अपनी पैदावार देने के लिए तैयार नहीं है । आप किसानों पर यह आरोप लगाते हैं कि हमने उन्हें पूरी कीमत दी है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आपने पिछले वर्षों में विदेशों से जितना अनाज का इम्पोर्ट किया था उसकी कास्ट 2639 करोड़ रुपये थी 1965 से लेकर 1973 तक आपने अनाज का इम्पोर्ट किया और 1973-74 के आंकड़े इस समय नहीं हैं । 1973-74 में 60 लाख टन का इम्पोर्ट किया । मैं समझता हूं कि इस सारे इम्पोर्ट में सरकार ने प्रतिवर्ष 230 करोड रुपया खर्च किया है । अगर यह 230 करोड़ रुपया सरकार किसानों को उनकी पैदावार के मूल्यों में बढोतरी करके देती, तो किसान इस अतिरिक्त मूल्य से फर्टिलाइजर खरीदता और इस तरह से एक किलो फर्टिलाइजर से 8 किलो अनाज का अतिरिक्त उत्पादन होता ।

इससे हिन्दुस्तान में फूड का प्राबलम सोल्व हो जाता, लेकिन आपने विदेशों को रुपया देने में संकोच नहीं किया जबकि हिन्दुस्तान के काश्तकार को मारने में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले अनाज के उत्पादन की समस्या का समाधान करना पड़ेगा । यह समस्या उसी हालत में सुधर सकती है जब हम किसान को भाव के सम्बन्ध में निश्चित करके चलें । यह बात सही है कि कुछ प्रगतिशील तत्व इस देश मे इस बात का नारा लगाते हैं कि किसान की प्रोप्राइटरशिप को समाप्त किया जाये, वे राजा-महाराजाओं के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ इस प्रकार के नारे लगाते हैं, लेकिन सरकार को इन नारों से सावधान होना पड़ेगा क्योकि वे छोटे बड़े काश्तकार किसी के पक्ष में नहीं है, वे पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप खत्म करने के पक्ष में है । आज जो वे व्हीटटैक-ओवर की पोलिसी का समर्थन कर रहे हैं वे इसलिए नहीं है कि वे कन्जयूमर के पक्ष मे है बल्कि जो उनकी पार्टी की नीति है कि पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप को खत्म किया जाये उसके समर्थन में किया है । वे जानते है कि एक व्यापारी बीच में से गायब होता तो किसान और सरकार के बीच सीधा रिलेशन हो जाता है और तब सारा दोष किसान के ऊपर डालकर उसे किस प्रकार से खत्म किया जाये उसके लिए वातावरण बनाया जा सकता है । सरकार ने उनका साथ दिया, सरकार भी फेल हुई, उन्होंने सरकार का साथ दिया और परिणामस्वरुप वे भी अपनी नीति को पूरा नहीं करवा सके ।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रोक्योरमेंट का पौइन्ट । प्रोक्योरमेंट--1972-73 मे 5 मिलियन टन के करीब हुआ, 1973-74 में 45 लाख टन हुआ और 1974-75 में मेरा ऐसा अन्दाजा है कि 18 लाख टन का प्रोक्योरमेंट होगा । अब एक बात का हम विचार करें कि प्रोक्योरमेंट कम क्यों हो रहा है । उसको मैंने अर्ज कर दिया । इसके साथ-साथ सरकार ने 105 रुपए का भाव निश्चित किया । मध्य प्रदेश ने 125 रुपए के भाव से गेहूं की खरीद की । बाकी राज्य सरकारों ने भी इनसेन्टिव दिए । राजस्थान सरकार ने भी किसानों को बोनस देने की बात कही थी । लेकिन आज किसानों को किसी प्रकार का इनसेन्टिव नहीं मिल रहा है । इसका नतीजा यह हुआ कि प्रोक्योरमेंट कम हुआ । इसके साथ-साथ जो सरकारी दुकानों की मार्फत डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें भी कमी आ गई । इसके परिणाम स्वरुप गेहूं की प्राइसेज बढ़ी, बाकी खाद्यान्नों की प्राइसेज बड़ी और बाकी उपभोकता चीजों की प्राइसेज भी बढ गई । इस सबका परिणाम यह निकला कि हिन्दुस्तान में ब्लेक मनी का जेनरेशन इतनी द्रुत गति से होता चला गया कि ब्लेक मनी की

एक पेरेलल सरकार बन गई। यह मैं ही नहीं कहता, हर सदस्य इस प्रकार की बात कहता है। ब्लेक मनी का जेनरेशन कैसे हुआ। आप चाहे जितने कन्ट्रोल लगाइए, आप चाहे जितने रेस्ट्रिक्शन्स लगाइए, लेकिन जब तक आप कन्ट्रोल्स को और रस्ट्रिक्शन्स को ईमानदारी से लागू नहीं कर सकते, सख्ती से लागू नहीं कर सकते तब तक कन्ट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शन्स का पालन नहीं होगा, उनका वायलेशन ज्यादा संख्या में होगा और जब वायलेशन होगा तो ब्लेक मनी ज्यादा जेनरेट होगा और वह ब्लेक मनी हमारी इकोनोमी को खराब करेगा। इस ब्लेक मनी ने जरूरत से ज्यादा इस सारी स्थिति को खराब किया है। प्रोक्योरमेंट के प्रश्न पर किसान और व्यापारी में अन्तर रखा गया। सरकार ने 105 रुपए पर व्यापारी से लेवी लेने की व्यवस्था की। उस आर्डर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गेहूं की किस्म क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, लेकिन सब राज्य सरकारों ने प्रोड्यूसर्स से जो लेवी वसूल की उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की कटौती क्वालिटी के आधार पर की जा सकती है। व्यापारी को छूट दी, लेकिन किसान को छूट नहीं दी। इसके बाद भी आपने व्यापारी को हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से को परमिट लेकर एक्सपोर्ट करने की छूट दी। व्यापारी को डिक्लेयर करने के बाद होर्डिंग करने दी, लेकिन किसान गेहूं की होर्डिंग नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, पहले सरकार ने घोषणा की थी कि लेवी केवल व्यापारी से लेंगे, लेकिन एक महीने के बाद सरकार ने घोषणा की कि हम किसान से भी लेवी लेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने किसान से लेवी लेने की घोषणा तब की जब बाजार के अन्दर काफी गेहूं आ गया। सारी स्टेट्स ने होर्डिंग के खिलाफ कानून बनाया और उसके आधीन 31 मई से कोई किसान 20 क्विन्टल से ज्यादा अनाज नहीं रख सकता था। उसके बाद राज्य सरकारों ने, किसी ने 10 जून से, किही ने 11 जून से, किसी ने 15 जून से प्रोड्यूसर्स से लेवी का आर्डर इशू किया। उसका परिणाम यह निकला कि किसानों ने प्रीवेंशन आफ होर्डिंग आर्डर से डर कर अपने अनाज को बाजार में बेच दिया।

जब उनके पास कुछ नहीं रहा तो सरकार ने लेविंग की और किसानों से जबरन सारा अनाज वसूल करने की कोशिश की। उदहारण यहां तक है कि पुलिस और मेजिस्ट्रेट ने घरों को लूटा है। किसानों ने बाजार से अनाज खरीद कर सरकार को 105 रुपये की लेवी में अनाज दिया है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा अन्याय जो हिन्दुस्तान की सरकार ने किया है उसका उदहारण पहले कभी नहीं मिल सकता। आज किसान ने 105 रुपये में अनाज दिया है और उस अनाज को व्यापारी ज्यादा दामों पर महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में जाकर बेच सकता है, लेकिन हिन्दुस्तान का किसान अपने राज्य के बाहर जा कर किसी भी प्रकार के अनाज को नहीं बेच सकता, बल्कि कई राज्यों में तो यहाँ तक पाबंदी लगा दी गयी कि किसान एक जिले से दूसरे जिले में भी अनाज नहीं ले जा सकता। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करना चाहूगा उपसभापति महोदय, की इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन्स या कंट्रोल अगर आप लगाय तो उत्पादन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रिब्यूशन को भी आप सामने रख कर चलें। 1973 में जितना अनाज राशन शाप्स के मातहत बिकता था उस को आपने 50 परसेंट कर कर दिया। आज हिन्दुस्तान में आप राशनिंग चलाना चाहते हैं, लेकिन आज तमाम राशन शाप्स बंद पड़ी हुई हैं। आज गरीब इन्सान अनाज के लिए तड़प रहा है और हमारी सरकार इस का प्रबंध नहीं कर सकती। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए और एक बात यह करनी चाहिए कि इन सारे कानूनों को हटा कर वह एक कानून हिन्दुस्तान में सख्ती से लागू कर दे और वह है होर्डिंग का कानून। सारे हिन्दुस्तान के खाद्य मंत्री मिल कर सारे खाद्य विशेषज्ञ मिल कर एक घोषणा कर दें कि व्यापारी के पास इतना अनाज रहेगा, हिन्दुस्तान में एक किसान के पास इतना अनाज रहेगा और इस से ज्यादा

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

जो अनाज रखेगा वह पकड़ा जायगा और उस के लिए आप को सख्त से सख्त सजा का प्राविधान करना चाहिए उस के बाद आप मार्केट को रेगुलेट करें। ऐसा करने से अनाज के भाव नीचे गिरेंगे और सरकार को जितना प्रोक्योरमेंट करना है वह आसानी से हो जायगा, लेकिन यह मान कर चले कि जितने रेस्ट्रिक्शन्स आप इंपोज करेंगे उतना ही उन को इम्प्लीमेंट करने में आप को परेशानी होगी। 1973 से आज तक 3,612 नोटीफिकेशन्स आर्डर्स और रूल्स भारत सरकार और राज्य सरकार ने इस संबंध में जारी किये हैं। आप अंदाजा लगायें कि इतने आर्डर्स और इतने रूल्स किसी सरकार ने भी जारी नहीं किये होंगे, लेकिन उस का परिणाम क्या निकला। परिणाम निकला भुखमरी और डेथ बाई स्टारवेशन। यदि यह परिणाम इतने आर्डर्स का निकलता है तो ऐसा लगता है कि सरकार के आर्डर्स से और नोटिफिकेशन्स से लोगों को एलर्जी है जिस का फायदा ब्लैकमार्केटियर उठाते हैं, प्राफिटियरस उठाते हैं और होर्डस उठाते हैं और बाकी लोग उस का फायदा नहीं उठा पाते।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिती में सरकार फूड कारपोरेशन के द्वारा काम कर रही है, लेकिन 1971 से लेकर 1973-74 तक फूड कारपोरेशन को स्टोरेज में लास हुआ, उस को ट्रांजिट में लास हुआ, उस को वेटेज में लास हुआ और कुल मिला कर 58 करोड़ रुपये का उस को नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि यह सरकार का काम था, यह किसी व्यापारी का काम नहीं था, या कोई नयी एजेंसी का काम नहीं था। आप के फूड कारपोरेशन को तीन वर्ष में 58 करोड़ का नुकसान होता है और इस को आप चैक नहीं कर पाये और इसका परिणाम है कि लोगों के सामने आप एक गलत आदर्श रख कर चल रहे हैं। इस लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा और खास कर अपने साम्यवादी मित्रों से, जो हमेशा कहते है कि व्यापारी से व्यापार छीनो, उन से खास कर कहना चाहूंगा कि गत वर्ष सरकार ने घोषणा की कि हम चावल का व्यापार अपने हाथ में नही लेंगे, जो राज्य सरकारें चाहें इस व्यापार को अपने हाथ में ले सकती है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। असम ने चावल के व्यापार को अपने हाथ में लिया, लेकिन केरल मे कम्युनिस्ट सरकार को इस बात की हिम्मत नही हुई। वहां यह घोषणा जरूर करते रहे कि इस व्यापार को वह व्यापारियों से ले लेंगे, तो क्या इस इल्जाम के दायरे में कम्युनिस्ट पार्टी नही आती। लेकिन मैं समझता हूं कि कहने में और करने में बड़ा अंतर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा उपसभापति महोदय, कि आप गेहूं के अंदर पूर्णतया फेल हुए हैं। आप गेहूं की नीति के संबंध में वास्तविक दृष्टि कोण ले कर चलें और वह तभी लिया जा सकता है कि जब सरकार के सामने मुनाफा कमाने का नही, बल्कि कंज्युमर और प्रोड्यूसर के हित में नीतियो को निर्माण करने की बात रहे और इस प्रकार की नीतियां तभी निर्धारित की जा सकती है कि जब उत्पादन बढ़े और उस को बढ़ाने की प्रेरणा हम किसानो को दें।

आप यह समझ कर चलें कि यहां पर एक बड़े जोर की हवा फैलाई जा रही है कि देश मे कुलक्स की संख्या बढ़ रही है। देश में बड़े छोटे और मध्यम काश्तकार हैं। मैं पहले यह नहीं समझ पाया कि हिन्दुस्तान में सीलिंग करने के बाद कौन से छोटे बड़े या इस प्रकार के काश्तकार आ गये? लेकिन दुनियां जानती है कि साम्यवादी मुल्कों ने जिस प्रकार की व्यवस्था की कि काश्तकार को श्रेणियों में विभाजित करो और एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी को लड़ाओ। अन्त में नतीजा क्या आयेगा कि काश्तकार की पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई ईमानदारी से खेती करके देखें, आज के मंहगे इन-पुट्स को खेती में लगाये और फिर देखे कि कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आती है। आज आपका जो किसान उस श्रेणी में आता है वह ट्रेडर है, उसको आप कुल्क कहें तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। उसका एक बड़ा कारखाना लगा है, 20 एकड़ का फार्म उसने कर रखा है, हाथ में एक मिल भी है। दूसरी जगह से ब्लेक मनी पैदा करता है और फार्म में

जाकर उसको वाइट करता है। इस तरह के लोग बहुत कम हैं। उनके आधार पर और उनके नाम पर अगर कोई गेहूं नीति बनायें तो निश्चित रूप से वह इस देश में सफल होगी। प्रोक्योरमेंट की जहां तक बात है, आपका प्रोक्योरमेंट वहां से होता है जिन किसानों के पास खाने को अनाज नहीं है, उनकी अनइकानामिक होल्डिंग्स है। अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए उनके पास साधन नहीं है . . .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): Why don't you tell how the procurement should be made?

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैंने आपको पहले कहा आप बाहर चले गये थे। मैं कहता हूं कि प्रोक्योरमेंट का एक ही तरीका है कि किसानों को उसके उत्पादन का पूरा मूल्य मिले। हमारी सरकार आ गई तो हम किसान को उसके उत्पादन का पूरा मूल्य देंगे और जितना जरूरी होगा उतना बफर स्टाक करेंगे।

श्री कृष्ण कांत (हरियाणा) : इस समय कितना मिलना चाहिए?

श्री भैरों सिंह शेखावत : आप सुनना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि 135 रुपये मिलने चाहिए।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I am sorry for interrupting. But I will have to reply to this. So I would also like to understand. When you are suggesting Rs. 135 as the procurement price, what should be the issue price for consumer? You are suggesting Rs. 135 as the procurement price . . .

श्री भैरों सिंह शेखावत : वह मैं बताता हूं। मैं कहता हूं कि आप सब्सीडाइज करके दो। सब्सीडाइज उस समय तक होगा जब तक आपकी फाल्टी पालिसी के कारण उत्पादन घटेगा, वितरण की व्यवस्था सुधरेगी नहीं। यह सब्सीडाइज करने का दोष हमारा नहीं है, यह इस सरकार का होगा, जिसने पिछले 20 वर्षों में खाद्य नीति में इतने घपले किये है कि उसको सुधारने में समय लगेगा और उस समय तक निश्चित रूप से आपको सब्सीडाइज करना पड़ेगा। वरना जैसे 1973 में आप फेल हुए, 1974 में भी आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप बतायें कि सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में क्या व्यवस्था कर रही है, जिसकी 50 परसेंट पापुलेशन बिलो पावर्टी लाइन है? उस जनता के बारे में कोई भी आप नीति बनायें। मैं समझता हूं कि उसको गहराई से सोच कर, काफी मनन के बाद बनायें। आपको मालूम है कि संसार में हिन्दुस्तान के व्यक्ति को सबसे कम कैलोरीज मिलती है ; इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। हिन्दुस्तान मिल्क के मामले में फिश के मामले मे, शुगर के मामले में, एडिबल आइल्स के मामले में लोवेस्ट लेवल पर है। 5 देशों में कहीं लोवेस्ट है, कहीं दूसरे नम्बर पर हैं, कहीं तीसरे नम्बर पर हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोई भी नीति बनायें वह नीति वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए। वह किसान और उपभोक्ता के पक्ष में होनी चाहिए, ट्रेडर के पक्ष में नहीं। आप बड़ी-बड़ी घोषणायें करते है कि व्यापारियों ने अपने वचन को नही निभाया और सदन में पूछते है कि व्यापारियों से आपने क्या वचन किया था तो कहते है कोई वचन नही किया। बीच में किस प्रकार से क्या समझौता हुआ, कोई नहीं जानता। आप व्यापारी पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन सदन का कोई माननीय सदस्य पूछना चाहे तो कहते हैं कि व्यापारी से हमारा कोई समझौता नहीं हुआ।

मैं समझता हू कि यह कोई प्यार की बात नहीं हैं जिसको आप प्रगट नहीं कर सकते। यदि आप व्यापारी से समझौता करते है तो आपको हिम्मत के साथ सामने आना चाहिए। आप इसलिए सामने नहीं आते, क्योंकि आपका वीक पौइन्ट है

श्री उपसभापति : नाउ यू वाइण्ड अप ।

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं ।

मैं समझता था कि आप नई नीति में ऐसा सुधार करेंगे कि काश्तकारों को जो अनाज देंगे उसका इन-पुट सस्ता करेंगे । मैं अपना एक नया अनभव बता रहा हू कि आज हिन्दुस्तान में एक काश्तकार लेवी के रूप में मिनिमम गेहूं दे रहा है । उस मिनिमम गेहूं पर जितना यूरिया उसे मिल सकता है वह ले रहा है । मैं बता रहा हू गेहूं की मार्किट प्राइस और प्रक्योरमेंट प्राइस जितना अंतर है उससे दुगुना अंतर यूरिया के कंट्रोल प्राइस और ब्लेक मार्किट की प्राइस में है । लोग इस गेहू के बदले में यूरिया का व्यापार कर रहे है । मेरा निवेदन है आप इससे सावधान रहें । इस गेहू की नीति की असफलता के संबंध में इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

SHRI KRISHAN KANT: Mr. Deputy Chairman, Sir, if the Government of India follows the food policy as was suggested by Mr. Shekhawat, we will be heading towards another catastrophe. I would like to deal with his points while making my submission, Sir.

Sir, last year, the Government took a decision to take over wholesale trade in wheat as a bold measure of a bold Government, committed to bring about structural changes in the society. If the hon. Members will remember, these were the words being used by many Ministers and supporters of the decision. As a matter of fact, it was a halting and much delayed decision. The country and the Congress had decided many times before to take over wholesale trade in foodgrains. But every time they slept over it. Sir, it will be interesting to go into the history of the idea of takeover in India. As I have spoken earlier, it is not a socialistic measure, whatever Mr. Shekhawat may say. It was a practical measure taken by a number of capitalist countries in the world. There is nothing socialism in this. It was a question of management. Sir, many capitalist countries in the world have taken over food trade for a number of years—say, Canada, Japan and Australia. Even in India, the first proposal to take over was not taken by the Congress Government. But after the Bengal Famine . . .

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): If you permit my interruption, in these countries, there is food surplus and the Government . . .

SHRI KRISHAN KANT: You speak whenever you get your chance. Now, let me make my submission.

Sir, after the Bengal Famine, during the War, when the British Government was ruling this country, a Commission called Woodhead Commission was appointed. It was that Commission which recommended the abolition of the wholesale trade. It was in the year 1943 that Lord Wavell had written to the then Secretary of State for India that British India was agreeable in principle to the removal of the wholesale trader. But they could not do it for the time being and they proposed to do it after the War. After the War was over, it was implemented and worked successfully for about two years. It is reported that the then Government had successfully exceeded the targets of procurement in U.P., Punjab, C.P. and other States. Then came the Asoka Mehta Foodgrains Enquiry Committee of 1958-59 which had recommended the takeover of wholesale food trade, excluding the pulses. Later on, many Congress resolution decided about it. And, Sir, when Shri Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister of India and the country was passing through a very difficult situation, it was at Durgapur Congress that the decision to take over food trade was taken. And Mr. C. Subramaniam was the Food and Agriculture Minister at that time. It was the Americans who suggested, "Why don't you have land reforms to have better production?" Because, in Japan, it was the land reforms which produced better food production. It is because when the people of the land feel a sense of involvement—not two or three per cent but the whole people—the production increases. Not only that, Sir. Later on, when the Congress was defeated in a number of

State Assembly elections in 1967, the ten-point programme was adopted, and the item of foodgrains takeover was a part of it. But it was not implemented. When the Congress was split, we adopted a charter for the nation in the Bombay Congress in 1969. The idea of food takeover was there. But again it was forgotten. Again in 1972, when the situation had started getting difficult, at Gandhinagar session, we adopted the resolution for the takeover of food.

4 P.M.

Sir, it was again the Woodhead Commission which first said that ensuring the reasonable quantities of foodgrains at reasonable prices to all the citizens of the country was the basic requirement of any civilised Government. It is much more fundamental than maintaining the rule of law or even the maintenance of law and order.

Sir, the Government last year, in 1973, had taken this decision to strengthen the distribution system of wheat by taking over this wheat trade after having experienced the difficulties of the economy for a number of years and much more after having experienced the behaviour of the trading community. But, Sir, what happened? When we took this step, it should have been realised that there will be criticism by the vested interests who were being removed and shifted from the economy. Sir, if you see clearly the situation you will find an interesting contract. When last year this policy was announced, there was a hue and cry in the vested monopoly press, in the Parliament and you could hear the echo in the Government circles also. But, when this year the procurement has been much less, do you find criticism in the press? The climate is not against criticism. Last year hue and cry was being made. That shows how the vested interests are powerful and trying to dictate to the Government of the country.

Sir, there might have been difficult views. I also, last year, was of the opinion that the prices of foodgrains should have been more. There should have been better preparation for the take-over of wheat trade. This separation should have started not from 1973 but from 1970 or 1969. Not only that. They should have given more inputs to the farmer. All those things are correct. But, Sir, instead of facing the difficulties, instead of meeting the propaganda of the vested interests and the warfare of propaganda; instead of removing the lacunae and deficiencies which were found in practice, Government surrendered and threw the baby alongwith the bath water. The question is why did not the Government start preparations from 1969 onwards? Sir, it may be remembered that the decision to take over was announced in April or May and within a period of four years the decision was given up. The decision in the A.I.C.C. in Gandhinagar was to take over wheat and rice trade in September. Without declaring their new policy and without taking the Parliament into confidence the Government gave up this decision and stealthily revised its policy. There must have been a private meeting between the traders and the Government. Some private commitment was made. We know only one thing that after the policy was announced by the Government, it was not Mr. Fakhruddin Ali Ahmad nor Mr. Shinde, it was Mr. Bhani Ram Gupta, General Secretary of the Foodgrain Dealers' Association, who announced in a press statement that it was he who was the real author of the policy. After the abolition of the traders in 1973 they decided to rehabilitate the traders in March, 1974 but continue to swear by the abolition of the wholesale trade. Whom the Government was deceiving all these months and all these years?

After ensuring the retreat from the take over policy to which the Government succumbed, with a tongue in check, Shri Bhani Ram Gupta announced that traders would not be bound by the commitment to procure 5 to 6 million tonnes at the ceiling price of Rs. 150 in the open market. They advised the Government to import wheat. I remember Mr. Shinde making a statement in this House saying that the whole idea of the new policy is to remove the psychology of deficits. In the statement made by Mr. Bhani Ram Gupta, he advised the Government to import food by creating a psychology of scarcity.

[Shri Krishan Kant]

Sir, when I wrote to Mr. Fakhruddin Ali Ahmed in April enquiring as to what was the position and whether any understanding was reached between private traders and him, he replied to me that the policy had been accepted and wanted it to be implemented without telling the truth about the arrangement that was arrived at and how the trader was being rehabilitated. A meeting of the traders was called. But, instead of threatening them to fulfil the commitment, the Government of India was threatening the Chief Ministers of different States, like Punjab and others to follow the policy and introduce the trader.

Government gave huge profits to the traders. Last year the procurement price was Rs. 76. This year it is Rs. 105—a jump of Rs. 29 per quintal, i.e., 40 per cent in one jump.

As Mr. Shekhawat said, wheat of all qualities was procured at the same rate as there is a saying in Hindi:

सभी धान बाइस पंसेरी

This policy failed in one month. After a period of one month, a second order was issued. In addition to the fifty per cent levy on wholesale trader, Government would also procure directly from the cultivator. What was the effect of all these measures? The trader was supplying the worst quality of wheat to the Government and selling better quality by himself. Sir, this is interesting. The procurement price was fixed at Rs. 105 and the market wholesale rate at Rs. 150. It means the Government itself accepted retail rate at Rs. 170 to Rs. 175.

What is the position today? The total procurement by both the methods, through Government and traders, is 1.75 million tonnes as against 4.7 million tonnes last year. Last year there was a chorus of voice that takeover policy had failed. All monopoly press, all vested interests were shouting about it. What about this year? Not a single word about it.

So far as the new policy was concerned, Punjab Chief Minister is on record that he was opposed to it. U.P. was not enthusiastic and so was Rajasthan. But the Government of India threatened them to accept and rehabilitate the traders. I raised this question on the floor of the House and I am sure, even now the Government has been forcing States to implement it. I would like to know who supported the policy. Perhaps those who knew nothing of the food and agriculture economy. Will the Government even now reveal who is the author of this policy? When Shri Bhani Ram Gupta announced in mid April that they would not honour the commitment of Rs. 150 ceiling price in open market, the Government did not act till the beginning of June, as pointed out by Mr. Shekhawat, and they statutorily fixed the price at Rs. 150. It was just locking the stable after the horses were stolen. In whose interest was the Government functioning?

Sir, bungling on food front is no less a serious crime in a poor country like ours than bungling on the war front. Government has shown so much helplessness and defeatism that even on 10th of July, after the new Agricultural Minister, Shri Subramaniam, took over, he called the meeting of traders. Mr. Subramaniam showed unhappiness and disappointment at letting down the Government and asked the traders to sumbit proposals within a week to ensure that more grains can be procured. Not only did he ask them to give proposals but also to list the difficulties that were facing them. What shall we call this attitude of the Minister? One is reminded of the Bourbon kings of France who learn nothing and forget nothing. The traders are not afraid of the warning of the Government. They know that you have been warning them for the last 25 years but you are not taking any action against them. They know you can take action against weaker people but not against profiteers. As in Hindi it is said:

न खंजर उठेगी, न तलवार उठेगी, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं ।

This is what the traders are feeling about the Government. Sir, it will be interesting to see the pricing pattern in various States, both official and market rates. The prevailing official rate in Punjab and Haryana is Rs. 150 while in deficit States it is Rs. 169. But the prevailing market rate is more than Rs. 200 and it is not even available

at that price in Delhi. Last year the market rate was Rs. 135 to Rs. 140. Now the official rate is Rs. 150 which is more than the black market rate in the last year. The present official rate is much more than the black market rate at which the wheat was available in the country last year. This is the result of your food policy for the poor people of India.

The target of procurement was 6 million tonnes. The actual procurement is 1.75 million tonnes. Last year the procurement was about 15 per cent to 20 per cent of the total wheat production and this year the total procurement has been, on the basis of the total production, 8 to 9 per cent or less than 10 per cent. By the change of policy, procurement reduced by less than half.

The hon. Minister himself said that there were two benefits out of the new policy: (1) Difference in prices between the deficit and surplus States have been narrowed down, and (2) market availability has increased.

Sir, the lower prices in Bombay and other places are not due to the new trade policy. They are because there have been better rains last year and better production in Maharashtra and that is the reason why the prices there are a little less.

Sir, the main point is, what is the price, not in Bombay because Bombay cannot control the wheat price for the whole country, but what is the price in the district towns in U.P., Bihar, Orissa and Madhya Pradesh? Last year, wheat was sold at Re 1/- a kilo. Now it is Rs. 2.50 a kilo. If you say that market availability has increased, I must say it is a blatant lie. If the availability of foodgrains is more, why are the prices more in the market? Even if the foodgrains are available, what are the prices?

Sir, about fixing of prices? Immediate increase of 40 per cent. You could have fixed up according to the increase in rates and costs. Sir, a good suggestion has been given that instead of increasing the price every year, it would be better if you correlate the procurement with the supply of outputs. May I know whether the Government has considered this suggestion given by Dr. Minhas about food money? It can stabilise the price and also give 11 to 13 million tonnes of foodgrains for your distribution system. What has been the result of your consideration.

[The Vice-Chairman (Shri Bipinpal Das) in the Chair].

There is perpetual inflation and weakening and shrinking of the public distribution system. Last year, 11 lakh tonnes of foodgrains had been issued monthly; now this year it is 4 lakh tonnes. This is to sustain a semblance of public distribution system.

Today the position is, Government is facing an unpredictable monsoon season with the lowest ever stocks in the history of the country. This is the greatest risk you are taking, Mr. Shinde, with the country, perhaps, greater than keeping the borders of the country unguarded. Hardly 2 million tonnes in the Central pool and 1 million tonnes in the States! We are again in for imports. You want to go in again for concessional food aid. And this is the note from the file of Mr. Subramaniam which has appeared in the press. I would not mind imports when the people are hungry but it must be once in a time. You must have a long-term policy so that you do not behave as you behaved in 1966-67 and left your priorities and all that. I am not against imports but you must have a long-term policy.

AN HON. MEMBER: We have permitted the Ministry.

श्री देवराव पाटिल (महाराष्ट्र) : आपने सरकार की पुरानी नीतियों के सम्बन्ध म तो बतला दिया और अब भविष्य की नीति के सम्बन्ध में भी बतलाइये ।

SHRI KRISHAN KANT: Mr. Patil want me to go to the bungling of the Seeds Corporation. I am not going into that at the present time. I will not interfere in that. All right; what are you going to do about the future? Are you going out of the rut? Your own assessment is, after the new kharif crop even, the prices will increase. Here I am reading from a paper, a Government paper which says:

[Shri Krishan Kant]

"There has also been a general rise in the prices and in the money supply in the country. Since these factors are likely to continue to operate for some time, there is little prospect of any respite from the continuing upward pressure on the foodgrains prices and even the arrival of the new kharif crop in October to November, 1974 may not bring about any significant change in this trend."

May I know from the Government if this is the policy? The only way out for you is, you must reiterate your basic decision to take over the foodgrains trade in all commodities otherwise you will not be able to check farmers shifting from one crop to the other. Procurement from the producer has to be the basic element which was decided in the Woodhead Commission, which was given by the Ashoka Mehta Committee and which was decided by the Congress resolutions.

Sir, the need to procure today is only for about 10—12 million tonnes of foodgrains spread over wheat, rice and coarse grains. Total food production in the country may be 104 million tonnes at present. So the total procurement has to be only just 10 per cent of the total production in the country. But you seem to have lost nerve. Can't this great country procure 10 per cent of the total production of foodgrains in the country?

Sir, I will end by quoting what Mr. Chalapati Rau wrote. "The basic question is that plans for efficient management of food economy are bound to go awry if the wholesalers, big farmers and corrupt officers and politicians are left free to operate as they have been doing in the past." Sir, I hope the Minister will give some candid reply and say what is the future policy.

DR. Z. A. AHMAD (Uttar Pradesh): Vice-Chairman, Sir, I do not want to quote figures. Everyone can . . .

SOME HON. MEMBERS: Nothing is left for you.

DR. Z. A. AHMAD: Every one can speak from his own angle. (*Interruptions*). I do not want to quote figures but I want and I demand that Mr. Shinde should accept in this House that his Department or the Department led by his senior colleague who is no longer here has failed and failed miserably . . .

SHRI RABI RAY (Orissa): His ex-colleague was also a farmer.

DR. Z. A. AHMAD: Please have mercy on me. As I said, failed miserably in tackling this problem.

SHRI V. K. SAKHLECHA (Madhya Pradesh): That results in promotion.

DR. Z. A. AHMAD: This problem has been with us for the last decade and a half or even more, how to provide for this poor country where nearly 50 per cent or more than 50 per cent of the people live below the poverty line, where uncontrolled trade goes on . . .

SHRI RABI RAY: It is 67 per cent.

DR. Z. A. AHMAD: Please allow me to speak. Otherwise I will sit down. Don't try to brief me because I won't accept your briefing. I will say whatever I have to say.

Where 50 to 60 per cent of the people are below the poverty line, how to provide them with cheap food, that is the problem of problems and the Government of India should have concentrated all its efforts, appointed competent people, and created an administrative machinery to solve this problem. This is the one issue on which the Government of India has failed totally.

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) : डा० अहमद एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं । आपकी राय में प्रोक्योरमेंट प्राइस और इशू प्राइस क्या होनी चाहिए ।

डा० जैड० ए० अहमद : आप जल्दी क्यों करते है ? मैं जवाब दूगा, लेकिन अभी नहीं ।

श्री चन्द्रमणी लाल चौधरी (बिहार) : क्या करना चाहते हैं यह भी तो बताइए ।

डा० जैड० ए० अहमद : अभी मैंने बोलना भी शुरू नही किया और आप चाहते है कि सब मसलों का हल बता दूं ।

They must have patience. Sir, you must control them. You must have patience to listen to all points of view. I submit that not only the voice is raised from this side —here there are different understandings; his understanding is very different from mine—but excepting for certain people who would not like to say anything or who have nothing to say either on this side or on that side—but from both sides that this reality has to be recognised and the nation must recognise this reality that you have not succeeded in providing cheap food to the most vulnerable sections of the society. That is the reality. Now it has been again and again pointed out to you that your policies are going out of balance and you have never accepted it; the Agriculture Ministry has never accepted it. Always they have been saying no, this time we are going to do it. I can go back to the long long period when Mr. Patil was the Food Minister. He said the whole problem would be solved; let us import under PL 480. All right, he imported but still the problem was with us. Then the new policy of take-over was adopted. We thought it was a good policy and we still think that that is the only policy that will ultimately succeed. You accused us of preaching dogmas. You said, you Communists talk of socialisation of trade, of nationalisation of trade and so on. But where do we stand today? I ask the entire nation. I say today this policy, excepting for our Jana Sangh friends who put forward the point of view of the hoarders and big farmers, is accepted by the entire nation that you must in respect of all essential commodities introduce the system of public distribution. Otherwise the whole society, the whole economy, will go to dogs. It is a sick and suffering society whatever you may say. You say you are bringing big structural changes, you are moving towards socialism and all that. How are you moving towards socialism?

When, as Mr. Krishan Kant said, you cannot get possession of 10 per cent of the foodgrains produced in this country in order to feed the poor people, your talk of socialism is meaningless. It is nonsense. Therefore, I would definitely say that it is high time that the entire Agricultural Department was reorganised; it is high time that competent Ministers were appointed there; it is high time that the entire structure of the secretariat of the Agricultural Department was looked into; it is high time that people responsible for again and again bungling in different ways the whole problem of food procurement and food distribution were transferred or given other jobs. Mr. Shinde is a knowledgeable person, and Mr. Shinde very often gives expression to very good sentiments. But I do not know whether Mr. Shinde is a prisoner of a whole clique in the Agricultural Department. In any case, I am very sure that his senior did not understand the problem. He is no longer here. If he were here in this House today, I am afraid I would have openly accused him . . . (*Interruptions*) No, no. The role of the person is there very much. I would have abused him of his inability to understand the problem, of his utter incompetence, of his inability to look at the problem. But he is not here. I do not want to say much. But I do insist that the Prime Minister should thoroughly examine the functioning of this Food and Agricultural Department and should see to it that a thorough overhaul of the whole department takes place.

SHRI KALI MUKHERJEE: Do you want the Prime Minister herself as the Agricultural Minister?

DR. Z. A. AHMAD: That is your problem, that is not my problem.

The point is, we left the policy of takeover of the wholesale trade. What was wrong with it? You say that you could not procure as much as you wanted. Why did you not procure? I have been from State to State, from Bihar down to South India. And I saw with my own eyes the complete absence of will on the part of the State Governments really to uphold that policy and to implement that policy. There was no political will; there was resistance on the part of the Chief Ministers; there was resistance on the part of the Food Ministers.

SHRI B. S. SHEKHAWAT: Even in Kerala?

DR. Z. A. AHMAD: I do not know about Kerala; it may have been in Kerala. I do not think Kerala is a heaven. I think all over the country there was lack of will on the part of the ruling circles in the States to implement this decision. Therefore, the matter moved swiftly and spontaneously and drifted and ultimately you procured merely 5 million tonnes. But even that performance was not bad. Instead of streamlining the administration, instead of tightening up the whole system, instead of plugging the loopholes, you have gave it up at the instance of the pressure of the wholesalers, the profiteers, the traders, the hoarders and the merchants who were responsible for it. Mr. Shinde, you are optimistic that you will get it. Who advised it? I am sure that there are some agents of the wholesalers and profiteers who are sitting in your Ministry at the top level who gave you advice, presenting a rosy picture before you that from these merchants you will get wheat. At the time when people like us who are often supposed to be dogmatists said that this would not work, you said, it is too early to give a verdict on that. You went on and on and on. It became such a miserable performance that you became the laughing-stock of people. When I say 'you', I do not mean you personally, I mean the whole department. The whole department became a laughing-stock. The merchants repudiated their word. They accused the producers and the producers said that they did not know where they stood, they did not know what price they would get ultimately out of it. The big producers, the big landlords and the big owners of land wanted to indulge in profiteering and the result is, neither the prices have come down nor have you stocks available. May be there is a little but that is not much of an availability. If the prices are high, what will the poor man do?

The availability may be there but the poor man or even people in an under-privileged position find it difficult to make both ends meet. Under what pressure have you been I should like to know. It is a matter of shame to us today that when you put questions whether you recognise that your policy has failed miserably, you say "No". We ask you, "Are you reversing your policy?", you say "No". Every time there is no reversal of policy. Every time there is continuation of the same policy. Every time it is a good policy. Every time your policy is successful. Every time you are going to turn the corner. And where is the head of this Department? He is now going to the Rashtrapati Bhavan. He says he is leaving enough food for the country for all time to come. You consider us to be children who would believe you in all your glib talk. The reality is this that unless you fundamentally examine the whole situation, Mr. Shinde, you will not succeed.

Mr. Subramanian has raised this question of agreement. The agreement is not working. We have looked at it. How will you proceed? You will have to adopt certain basic principles, and the basic principle is enunciated by Mr Krishan Kant. Take straight from the producer. Do not bring in middleman. As long as middlemen are there profiteering will go on. You cannot have two things at the same time. You cannot allow profiteering and hoarding to co-exist with a system of proper distribution of foodgrains, the two cannot co-exist. Either there is a proper public distribution of foodgrains for the people by eliminating hoarding and profiteering or allow profiteering and hoarding to go on and then do not talk about introducing proper distribution of foodgrains for the two cannot co-exist. You have to base your whole policy on certain principles. Please enunciate your principles. Mr. Shinde, up to date no principles have been enunciated. Mr. Subramaniam is again and again saying that you have to re-examine your policy. We have to do something about it. But I want that the new policy should be based on the policy of direct procurement from the producer. Let there be a net work of public distribution not only of wheat but of other foodgrains otherwise the law of economics will apply, namely, you cannot control one thing and

leave the substitutes uncontrolled. They will influence each other's price. Wheat will influence rice. Rice will influence bajra. Bajra will influence jowar and so on. All these commodities are inter-related because they are exchangeable commodities.

Then abolish wholesale trade in foodgrains by merchants. Abolish it. And you can manage with a powerful machinery, with such big leaders who have recognition all over the world. Can you not do it? It may be ironical. But the fact is this that we have a good image in the world. I feel really ashamed when I go out because they have been reduced to the position of international beggars, an international beggar begging for food. Many people ask me: You are such a big country with such a big hard-working population and still you beg, can't you produce enough to feed your people, just grains, not high quality food, just starch to give your people? This is because while you talk of structural changes, while you talk about socialism your entire policy is based on disgusting pragmatism. You have no principles. This thing will not work. Some pressure here and some pressure there. Your principles have to be defined. Let us not go as international beggars to the givers' court. Already there are nations which are insulting us. They say, "Oh, after sometime you are going to come with a beggar's bowl before us". Let us keep our dignity. It is not only a problem of livelihood; it is a problem of the nation's honour. If we can feed our people, we can go with our head high. If we cannot do that, we will have to look low and beg for food. Therefore, Sir, as you have rung the bell twice, I might end here. The Prime Minister is not here. But she knows everything that is going on. I think she has learnt the reality of this, that the Food and Agriculture Ministry is one of the most inefficiently run Ministries in the whole set-up. Therefore, a thorough overhauling of this Ministry, both at the ministerial level and at the secretariat level, has to be brought about. That is one thing. Then, Policies should be based on firm principles, not on pragmatism. Firm principles should be enunciated and these firm principles should be implemented in the form of a policy and implemented with strictness, with courage, with honesty. You should see that your lower rungs of administration abide by them. You should see to it that the policy is not only accepted by the ruling party, but it is implemented by the ruling party. Violations of those policies should be punished in your own party. If you don't do that, how long will you carry on like this?

I have stated what I wanted to say. I hope that in the near future the nation will know what the new policy is going to be. Then we shall get an opportunity. I hope that this great country of ours, this great land of ours, will not continue to suffer and starve. I hope that this great land of ours will develop the internal economy, and particularly agriculture and food in a manner that we can hold our head high in the community of nations and not be a pitiable beggar nation that we have reduced ourselves to now. Thank you.

SHRI R. K. MISHRA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, the discussion on the wheat policy to-day, I think, is a discussion on a subject which is of paramount national importance not only from the point of view of stabilising the economy and reversing the hyper-inflation which has gripped the country, but also from the point of view of preserving the democratic system which we have built in the country during the last 26 or 27 years. The food crisis and the mismanagement of the food economy during the last few years has created a situation which threatens the entire fabric of our society and threatens to assume the proportions of a serious law and order problem in various parts of the country. My hon. friend, Shri Shekhawat, said that it was a bad day, it was a sad day, on which the decision to take over the wholesale trade in wheat was taken. In fact, Mr. Vice-Chairman, I think that was a day which gave us confidence . .

SHRI KALI MUKHERJEE (West Bengal): The only day.

SHRI R. K. MISHRA: Yes, that was a day which gave us confidence that we would be able to move in a direction whereby the crores of people in India living below the poverty-line may be able to get foodgrains at a stable price and in adequate quantity over a long period of time. Anyway, at best we can say that the giving up of that policy has been a very short-sighted step taken out of lack of conviction; or, at worst, we can describe it as a panicky capitulation to the propaganda barrage of vested interests and reactionary elements in this country. But before I proceed further, Mr. Vice-Chairman, I will concede that my friend, Dr. Z. A. Ahmad—he has left—and people like me and Mr. Krishan Kant, who support the policy of take-over, also fell a prey to that propaganda. Even to-day Dr. Ahmad was saying that the policy did not succeed. That is exactly the mischief that was done during those fateful days.

The Agriculture Ministry fixed a target of 8 million tons of procurement of wheat. It was an unrealistic target that was fixed. It was a target which was fixed on the assumption that Rs. 150 crores which were provided for the crash rabi programme would be utilised properly and the shortfall of 15 million tons in kharif that year would be more than made good in the rabi programme. But the report of the Comptroller and Auditor General has now revealed that the Agriculture Ministry and various agencies in the State Governments who were provided these funds, mis-spent them and misappropriated them and did not utilise these funds for increasing agricultural production under the special rabi crash programme. In fact, the money that should have been used for increasing agricultural production was used in some States for such un-productive activities like purchase of luxury motor cars.

[The Vice-Chairman, (Shrimati Purabi Mokhopadhyay) in the Chair].

Therefore, Madam Vice-Chairman, I say it was a wrong and artificial and unrealistic target that was there. Secondly, from the very beginning those who were in charge of administering this policy had no heart in it. A committee had been set up under the chairmanship of a Member of the Planning Commission, Prof. Chakravarti to study how to implement the scheme of take-over of wholesale trade in wheat. The committee made 17 suggestions as to how to make this scheme a success. Fifteen out of those 17 suggestions were not implemented at all by the Government. The committee had also indicated that it would be appropriate to give a remunerative price, a little more than Rs. 76 to the farmers at that time. The honourable Minister, Shri Shinde, at that time firmly declared, we will not give one rupee increase to the farmers. And in between a new scheme of bonus was floated and an impression was created that the Government was dilly-dallying and was not sure about the whole thing. And thus from the very beginning the whole programme was sabotaged. The honourable Shri Shekhawat said that the price has increased because of the take-over. No. What exactly happened was this. It was a period of scarcity. If you remember, it was a period of acute scarcity in the country. The Government had a stock of 9 million tons of foodgrains with it. And instead of preserving and distributing these 9 million tons through the public distribution system, they went on selling this stock in the open market at the rate of 1 million tons a month. And it was only when the stocks had been depleted that they said they stopped this whole process. Therefore, what I am saying is that the target of 5 million tons that year could have been proper and realistic. And if we look at the achievement, at Rs. 76, 4.7 million tons were procured, and I think it was a miraculous achievement of which we should be proud. And we should not have fallen a victim to the propaganda. As I said, all of us fell a victim and in Dr. Ahmad's party's paper 26 articles were written and all the 26 articles stated that the scheme had failed. Therefore, when there was a climate in the whole country that the scheme had failed, in that climate vested interests took advantage and led the Government up the garden path in reversing that policy. I would also like to point out that those of us who support this policy, failed in our

duty. As far as mobilisation of the farmers is concerned, we did not do enough to go to the farmers, to explain to them the rationale of this policy, to explain to them how it was crucial for preserving our national independence and for pursuing the path of self-reliance. We did not secure their support and since it was not done, since mass mobilisation in support of this policy was not done, all of us, along with Shri Shinde, share the responsibility for the failure on this front. Let us be candid and let us be honest about it. I would like to remind the honourable Shri Shekhawat that both of us come from a State which is frequently visited by drought and famine, though he has migrated to Madhya Pradesh for purposes of coming to this House . . .

SHRI B. S. SHEKHAWAT: As you have migrated to another profession.

SHRI R. K. MISHRA: Both of us come from the State of Rajasthan where we had frequent droughts, say 11 years out of 14 years. Therefore, what would happen if the Government does not have the stocks? How will they distribute foodgrains to famine stricken people, if they had not taken over wholesale trade in wheat in that year? There were 15 crores to 16 crores of people in various States like Maharashtra, Rajasthan, parts of U.P. and parts of Bihar, Orissa and Andhra Pradesh who were in the grip of one of the most severe droughts. It would have been impossible to feed them and it was only because this step was taken that it was possible for the public distribution system to cater to their needs . . .

श्री भैरों सिंह शेखावत : पिछले वर्ष ग्रेन टेक-ओवर में 5 लाख मिलियन का प्रोक्योरमेन्ट हुआ था।

SHRI R. K. MISHRA: That is another point. He may say that there had been famines earlier also and how the Government was maintaining the public distribution system during that period. In 1965-66 when we had a similar famine, we distributed about 13 million tonnes of foodgrains. But two-thirds of it were imported from the United States of America under the P.L. 480 programme. Government has been reducing the quantum of imports over the years and therefore if we want to have self-reliance, if we want to have national honour and self-respect and at the same time want to ensure supply of foodgrains to the vulnerable sections of our people, especially in areas of scarcity and drought, there is no other mechanism but to have public distribution system. Public distribution system cannot be a temporary thing. It cannot be created overnight. It must be built over a period of time and the Government must have enough stocks. How to have enough stocks? This is the problem. Once you admit that there should be public distribution system in our country, it will be necessary to suggest some ways and rightly the Minister enquired from Shri Shekhawat who had no reply to it except that the price should be fixed at Rs. 135 which is an absurd suggestion . . .

SHRI B. S. SHEKHAWAT: Absurd for you, not for the producers.

SHRI R. K. MISHRA: I will come to it in a minute. Therefore, the main problem is how to ensure that the public distribution system works well. It is not a dogmatic question. It is not an ideological question. It is a pure and simple practical question, as Shri Krishan Kant has pointed out.

Public distribution system in our country, at the moment, covers about 16 million people under statutory rationing and another 396 million people are covered under informal rationing. In fact this is not enough. If we want to cover even 50 per cent of those people who are under the poverty line, we will have to have a public distribution system which may distribute about 20 million tonnes of foodgrains. These 20 million tonnes of foodgrains cannot be procured by purchases in the open market. I would like Shri Shinde, to point out whether it could be done by a direct levy on producers (*Time bell rings*). Acharya Vinobha Bhave has made a suggestion. He says that land revenue should be one-sixth of the produce and it should be collected in the form of grains. This will fetch

[Shri R. K. Mishra]

to the Government at the present level of production about 17 million tonnes of foodgrains Whether those vested interests and entrenched interests who opposed the take-over of wholesale trade would allow implementation of this or not has to be seen.

My last point is that we cannot discuss the problem of distribution in isolation from the problem of production. Therefore, I would like to point out only two or three points in a couple of minutes ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Your time is up.

SHRI R. K. MISHRA: Last point.

We must remember, Madam, Vice-Chairman, that as far as agricultural production is concerned, it is not that production has suffered due to lack of investment. In fact, till 1964, agricultural production was increasing at the rate of 3 per cent, when agriculture was neglected and heavy industries were encouraged. After that it has declined., There has been substantial increase in the production of wheat, but not in production of rice, pulses and coarse grains. The production of coarse grains after that has stagnated. There was not enough increase in production of rice. The production of pulses has also declined. Wheat constitutes one-fourth of the total foodgrains consumption in our country. Therefore, unless the entire production strategy is changed and production in other foodgrains is increased, it will not be possible to have a viable policy only in regard to wheat. You must have a policy in regard to production of all foodgrains and distribution of all foodgrains through the public distribution system . . . (*Time bell rings*).

Lastly, Madam, Vice-Chairman, I would like to say that production will not increase unless the marginal and small farmers are given inputs. There are two crores of them who produce ten million tonnes of foodgrains. Their production can be increased to 60 million tonnes if only inputs are given. As long as the policies which are in favour of the traders, which are in favour of the hoarders, whether in the rural areas or in the urban areas, continue, we will continue to have food crisis, and foreign countries inimical to us will always on the look-out to twist our arms as they did in the mid-1960s. A new, viable agricultural policy, based on mopping up the marketable surplus by the Government —whether you call it nationalization or whatever you call it—should be there. And only such a policy will ensure that we have self-reliance and we supply foodgrains to the vulnerable sections of the people.

श्री बनारसी दास : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह समझता हूं कि सरकार की गेहूं के सम्बन्ध में कोई पालिसी ही नहीं है । 1973 में सरकार ने गेहूं को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया था और उस समय होलसेल ट्रेड को एक्सक्लूड करने का विरोध नहीं था । प्रश्न यह था कि किसानों को उनकी पैदावार की रिम्योनरेटिव प्राइस दी जाए और यह प्राइस उन्ह न मिलने के कारण सरकार की नीति फेल हुई । उस समय गवर्नमेंट को केवल 43 लाख टन ही अनाज मिल सका जबकि बिना ट्रेडर्स को एक्सक्लूड किये सरकार को 50 लाख टन अनाज मिला था ।

अब इस साल गवर्नमेंट ने अविवेकपूर्ण तरीके से व्यापारियों के सामने समर्पण कर दिया । सरकार की जो नीति थी वह साइन्टिफक नीति नहीं थी । सरकार की नीति की वजह से गेहूं के दो भाव हो गये और बाजार के अन्दर अनाज न आने का मुख्य कारण यह था कि गवर्नमेंट ने किसानों के लिए गेहूं की खरीद कीमत 105 रुपया क्विन्टल कर दी । व्यापारी लोग किसानों से 105 रु० के बजाय 115 रुपये क्विन्टल में गेहूं खरीदने लगे । आधा गेहूं तो उन्होंने सरकार को लेवी के रूप में दे दिया और आधा गेहूं उन्होंने बाजार में 160 और 165 रुपये क्विन्टल में बेच दिया । जो गेहूं व्यापारी ने लेवी के रूप में सरकार को दिया वह तो 105 रुपये के हिसाब से दिया । मैं उत्तर प्रदेश की बात जानता हू । मेरा जिला बुलन्दशहर, जो उत्तर प्रदेश का ग्रेनरी

कहलायी जाता है, उसने पार साल 2 लाख टन अनाज दिया था। इस साल सरकार ने किसानों से सीधे 105 रुपया क्विन्टल गेहूं खरीदा। व्यापारियों ने आधा अनाज तो लेवी के रूप में सरकार को दिया और आधा खुले बाजार में बेच दिया जो कि 160 और 165 रुपया क्विन्टल था। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापारियों को 50 किलो अनाज साढे बहत्तर रुपये में देना पड़ा जिसमें ढाई रुपया तो खर्चा हुआ और ढाई रुपया सेल्स टैक्स पड़ा। व्यापारियों ने लेवी का गेहू सरकार को देने के बाद भी बाकी जो गेहू बचा उसको काफी कीमत पर बाजार में बेचा। इसका नतीजा यह हुआ कि मार्केट में गेहूं के दाम 165 और 180 रुपया क्विन्टल तक पहुंच गये। जब बाजार में गेहूं के भाव इतने ज्यादा बढ़ गये तो किसानों ने सीधे कज्यूमर्स को गेहू बेचना शुरु कर दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि देश में गेहूं का अभाव हो गया।

कन्ज्यूमर ने यह समझ कर कि आगे अनाज मिलना मुश्किल होगा खरीदना शुरु किया। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जहा के व्यापारियों का सहयोग मिलता वहां का सारा का सारा अनाज खरीद लेती। गवर्नमेंट ने सोचा कि यह भी चावल की लेवी की तरह ले लेंगे। पैडी किसान अपने घर पर नही रख सकता। पैडी से चावल बनाने की मिले सीमित है। उनसे गवर्नमेंट लेवी ले सकती थी। गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा इनडिसक्रीशन यह किया कि उसने दो प्राइसेस बनाई। व्यापारी से कहा कि इन्टर-स्टेट व्यापार पर कोई पाबन्दी नही होगी जबकि फैक्ट यह है कि पाबन्दी हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को व्यापारी का सहयोग भी नहीं मिला। स्केयरसिटी उतनी नहीं है। पिछले साल 26 मिलियन टन अनाज हुआ था तो अब की बार 24 मिलियन टन अनाज हुआ है। आज क्या है? मुजफ्फरनगर में, कल की रिपोर्ट के मुताबिक, दो रुपए पर किलो अनाज बिक रहा है, बुलन्दशहर में दो रुपए किलो अनाज बिक रहा है। बम्बई के अन्दर, एक सदस्य ने कहा, पौने तीन रुपए अनाज बिकता है। आखिर इसका हल क्या है? अभी कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट को बुलनरेबिल सेक्शन्स को जो 40 परसेंट है, अनाज सप्लाई करने की व्यवस्था करनी चाहिए सस्ती दरों पर। जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा कि 135 रुपए पर सरकार खरीदे और गवर्नमेंट सबसिडी देकर कन्ज्यूमर को दे। आपका तजुर्बा क्या है? पांच साल में आपका खर्चा रहा 30 रुपए और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेज रहे है 20 रुपए, कुल हो गया 50 रुपए। अगर बुलनरेबिल सेक्शन को 40 परसेंट माने तो वह 22 करोड़ 40 लाख हो गया और अगर 345 ग्राम प्रत्यक व्यक्ति को अनाज दें तो कम से कम 30 मिलियन टन अनाज आपको चाहिए साल भर के लिए, जिस का मतलब यह है कि आप 50 रुपए सबसिडी दें। इस तरह आपको 1500 करोड़ रुपए की सबसिडी देनी होगी। अगर आप के एडवाइजर मिस्टर अहमद हैं तो उनकी नीति यह है कि आप 1500 करोड़ रुपये का और कर लगाइए ताकि एक-दो साल में---आज रुपए की कीमत घट कर 30 पैसे हो गई है---इन्डोनेशिया की तरह और जर्मनी के मार्क की तरह गवर्नमेंट आफ इंडिया बैंकरप्ट हो जाय, तनख्वाहें न दी जा सकें, फिर यहा पर एक कूप हो और डैमोक्रेसी नष्ट हो। मिस्टर कृष्ण कान्त ने कहा कि एक करोड़ टन अनाज की जरूरत है। एक करोड़ टन अनाज की सबसिडी क्या होगी? पिछले साल आपकी सबसिडी 260 करोड़ रुपए थी। इस साल आपकी सबसिडी क्या होगी? अगर आपका गेहूं का कन्जम्पशन तीन करोड़ टन हुआ तो जैसा आपका महकमा है, उसका लास उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। मिस्टर शेखावत ने तीन साल के आंकडे दिए। उत्तरोत्तर क्या हुआ? अबकी मर्तबा 73 में आपका लास 22 करोड 24 लाख रुपए का रहा, उससे पहले 17 करोड़ और उससे पहले 18 करोड़ था। अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन करोड़ टन हो गया तो आपके लास का एवरेज 66 करोड़ हो जायगा। इस साल के अन्दर, रेलवे को मिला कर, आप करीब 600 करोड़ के कर पहले ही लगा चुके है और इस तरह 1500 करोड़ रु० के कर और लगाने पड़ेंगे।

[श्री बनारसी दास]

40 परसेंट बुलनरेबिल सेक्शन के लिए डा० अहमद फाइनेंसेज कहां से प्रोवाइड करेंगे। आज रशिया, चाइना जैसे बड़े बड़े देश क्या खाने के मामले में स्वावलम्बी है ? अमेरिका ने पिछले साल विदेशों का गेहू कारनर कर लिया और फिर दूसरे देशों को दिया, हमको भी दिया राजनीतिक दृष्टि से आब्लाइज करने के लिए।

तो श्रीमन्, मैं मिस्टर शिन्दे से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप की कोई प्लानिंग है, क्या आप की कोई थिंकिंग है। यह जो आप का फूड कारपोरेशन है यह एक सफेद हाथी है। मैं यह मानता हूं कि बफर स्टाक आप को बनाना पड़ेगा, मैं यह मानता हूं कि फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम आप को बहुत हद तक अपने हाथ में लेना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि डा० अहमद ने कहा कि वीकर सेक्शन को पहले लीजिए। तो 40 परसेंट के हिसाब से वीकर सेक्शन साढ़े 22 करोड़ लोग होते हैं। तो उन के लिए बहुत से स्टैगरिंग फीगर्स हो जायेंगे और अगर आप सारे देश के लिये खाने का इंतजाम करें तो आप का माध्यम क्या होगा . . .

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : क्या करना चाहिए ?

श्री बनारसी दास : मैं वही बतला रहा हूं कि क्या करना चाहिए। आप को यह करना चाहिए कि सीधे किसान से निश्चित भाव मुकर्रर कर के आप गेहूं खरीदें। लेवी का सिस्टम जिस में दो मार्केट पैदा होते हैं, इस को आप बिलकुल खत्म करें और यह कहना कि होल सेल ट्रेड को अबालिश कर दें तो ऐसा आप यह समझ कर कीजिए कि कृष्णकान्त जी तो कहते हैं एक करोड़ टन की बात और डा० अहमद साहब के हिसाब से अगर वह जमीन पर आकर हिसाब लगाये तो उन के हिसाब से आप को 3 करोड़ टन अनाज प्रोक्योर करना चाहिए ताकि कम से कम 60 परसेंट आबादी को खिलाया जा सके। हमारे जैसे स्टेट में डा० अहमद का जिला है, देवरिया, वहां आप डेफिसिट ऐरियाज में अनाज भेजेंगे कैसे अगर यह होलसेल ट्रेड नहीं होगा तो। इस साल क्या हुआ। एक ही इलाज है कि आप सीधे सीधे कहिये कि किसान से एक एक दाना ले लिया जायेगा और हर जगह राशनिंग होगी। हर एक आदमी के लिए राशनिंग होगी। डा० अहमद तो गवर्नमेंट के सलाहकार हैं।

डा० जैड़० ए० अहमद : मैं इस को एब्सडिटी पर रिड्यूस नहीं करता।

श्री बनारसी दास : मैं उसी पर आता हूं। डा० अहमद के मुताबिक 40 परसेंट आबादी को खिलाने के लिए 3 करोड़ टन अनाज की जरूरत है और यह है 345 ग्राम फी व्यक्ति के हिसाब से, इस ऐवरज से चूंकि इस में बच्चे भी शामिल हैं। तो क्या तीन करोड़ टन अनाज आप ले सकेंगे ? क्या आप 15 सौ करोड़ की सब्सिडी दे सकेंगे तो मेरा कहना यह है कि एक करोड़ टन अनाज आप प्रोक्योर कीजिए और आप इस को सीमित रखिये गवर्नमेंट सर्वेंट्स और कुछ दूसरे तबकों तक और इस इंटर स्टेट रिस्ट्रिक्शन को दूर कीजिए। दूसरा प्वाइंट मैं यह अर्ज करना चाहता हू मिस्टर शिन्दे से कि महाराष्ट्र ने 700 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर पर खर्च किया है (*Time bell rings*) मैंने तो अभी पांच मिनट ही लिये हैं। तो वहां सारा का सारा कैश क्राप्स पर जोर है। गुजरात में सारा का सारा जोर कैश क्राप्स पर है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और केरल सारी कैश क्राप्स बना रहे हैं और उन से उनको इन्कम ज्यादा होगी और उन के लिए कालोनीज हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश ज्यादा सरप्लस नही है। तो यहां के लोग चीप ग्रेन पैदा करेंगे और उस को गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। वहां की कपास पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, सीमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोकोनट आयल और ग्राउंड नट पर कोई कंट्रोल नहीं होगा और इस प्रकार महाराष्ट्र के किसान को यू० पी० के किसान से दुगनी रकम मिलेगी और कोई रैशनल

नहीं होगा और न आप उस टेकओवर करेंगे । सीमेंट का दाम बढ़ता चला जायेगा । तो सब से पहले आप रीजनल सेल्फ सफीशियेंसी पैदा कीजिए और इस बात पर गौर कीजिए कि जैसी महाराष्ट्र की स्थिति है, गुजरात की स्थिति है वहां ज्यादा फूडग्रेन्स नहीं है, लेकिन वेजीटेबिल आयल के लिए मूगफली है और वेजीटेबिल आयल के दाम आज आसमान पर चले जा रहे हैं, कपास के दाम आज आसमान को छू रहे हैं, जूट का दाम जब तेज होता चला जायेगा तो क्या आप समझते हैं कि फूडग्रेन स्टेट्स आप की कोलोनीज बन कर रहेंगे ? कोई न कोई अनुपात होना चाहिए । 5 P.M. तो आप एक रेशनल पालिसी बनाइये इधर आपने 30 रुपया क्विंटल खर्चा किया । यह आपका जो फूड कारपोरेशन है यह बिलकुल सफेद हाथी है और इसमें एक-एक दो-दो करोड़ के ऐक्सपेंसेज हैं । मैं सहमत हूं डा० अहमद से कि उसे खत्म किया जाए और फूड कारपोरेशन को नया बनाइये । जिस तरह से कोयर्शन चल रहा है अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में लें तो आपके चपरासी का वेतन जैसे एल० आई० सी० में 500 से कम नहीं होगा, क्लर्क का 800 से कम नहीं होगा तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्चा 1 रुपये पर 50 पैसे से कम होने वाला नहीं है । जैसे जैसे रेलवे ने स्ट्राइक किया, बिजली ने स्ट्राइक किया अगर फूड के महकमें ने स्ट्राइक कर दिया तो एक दिन में काफी नुकसान हो जाएगा । लिहाजा इसमें आप रोज-रोज वेरियेशन मत कीजिए इसको गोट बनाने की कोशिश मत कीजिए । फूड ग्रेन की पालिसी का ताल्लुक राजनीति से न रखिये । थोड़ा जमीन पर आकर प्राइम मिनिस्टर को राय दीजिए क्योंकि मैं जानता हूं कि आप तो असमर्थ हैं । इसमें सारे विरोधी दलों के लोगों को बुलाइये । आप गैम्बुल कर रहे हैं लोगों के जीवन के साथ । जो गुजरात में हुआ वह क्यों हुआ ? गुजरात के विद्यार्थियों को नरिशमेंट नहीं मिलता था, उनको खाना नहीं मिलता था । बिहार का विद्यार्थी आज भूखा मरता है । तो विद्यार्थियों में यह पोलिटिकल एजिटेशन नहीं है, यह भूख की आग है जिसने बिहार को जलाया है, जिसने गुजरात के शासन को भस्मसात कर दिया । इसको आपने कंट्रोल नहीं किया और आप गैम्बुल करते रहे और कभी आप किताबों से छूरी निकालकर लायें, कभी आप प्रैगमेटिज्म का नाम ले तो इस तरह से मुल्क के साथ खिलवाड़ न किया जाए । मिस-गवर्नमेंट और जगह बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन खाने के साथ ऐक्सपेरिमेंट मत करिये । मैंने अर्ज किया कि इसको आप अपनी पार्टी की पालिसी न बनाकर नेशनल पालिसी बनाइये । जैसे-जैसे आप अनपापुलर होते जा रहे है, जैसे-जैसे आप जनता से हटते जा रहे हैं तो फिर आप गैमिक्स के अन्दर पड़कर नेशनलाइजेशन का नाम दे दें यह ठीक नहीं । यह नेशनलाइजेशन है ? यह जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, यह तो पनाहगाह है । इकबाल सिंह हटे । उसके ऊपर कौन सा मुकदमा चलाया गया है ? आज जितने भी पब्लिक सैक्टर हैं आज हम कहते है कि पब्लिक सैक्टर्स हैं, जैसे रेलवे है, रेलवे में ज्योति बसु ने प्राइम मिनिस्टर को बिलकुल फूल-प्रूफ अलीगेशन का चार्ज दिया लेकिन एल० एन० मिश्रा बैठे हुए हैं । इधर अमरीका था । अगर यह डेमोक्रेटिक मुल्क है तो इसमें विरोधी पक्ष का सवाल नहीं है, विरोधी बैरियर्स को पार करने के बाद जहां तक क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, जहा तक भ्रष्टाचार का सवाल है, फूड पालिसी का सवाल है, आप एक नेशनल पालिसी बनाइये । सब लोगों की सलाह लीजिए । अहंकार में, दम्भ में आकर 3 साल से आपने जनता की जिन्दगी के मसले को बढ़ाया है, जनता की जिन्दगी के साथ आपने खिलवाड़ किया है, । आप वह खिलवाड़ मत कीजिए । आप एक फूड पालिसी बनाइये मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।